वर्ष 64 ▸▸ अंक 58 ▸▸ पृष्ठ 12+4=16
भोपाल, रविवार 22 नवंबर 2020
कार्तिक शुक्ल पक्ष 08, विक्रम संवत 2077
महानगर ▸▸ मूल्य 3.50 रुपए
आज के अंक के साथ संडे जागरण

दैनिक जागरण

खबरों में सबसे तेज एवं विश्वसनीय अखबार

शुभ रविवार

सब कुछ यथावत् और सुंदर रहेगा। बस आप खुद को सुरक्षित रखें

कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें।

www.jagranmp.com/epaper

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की उड़ान पर लगा ब्रेक

बैंकों के आंकड़ों से हुआ खुलासा: विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रों ने बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए नहीं दिए आवेदन

कोरोना ने रोकी रफ्तार: पिछले सालों की तुलना में एजुकेशन लोन के लिए अब तक आए महज तीस फीसदी आवेदन

विवेक झा, भोपाल

मध्यप्रदेश से पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की उड़ान पर ब्रेक लग गया है। ऐसा इसलिए कि विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। ऐसे छात्रों की संख्या लगभग नहीं के बराबर रह गई है। उनकी रफ्तार पर ब्रेक कोरोना ने लगाया है। कोरोना के कारण अभिभावक अब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने से कतराने लगे हैं। विदेशों के अलावा सामान्य एजुकेशन लोन के लिए भी पिछले सालों की तुलना में महज तीस फीसदी आवेदन आए हैं।

पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाने वाले छात्रों का खुलासा खुद बैंकों के आंकड़े कर रहे हैं। जो लोग पढ़ाई के लिए बच्चों को विदेश भेजते हैं, उनमें से ज्यादातर बैंकों से एजुकेशन लोन लेते हैं। इस बार विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेने में लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी मानसिकता पर कोरोना का असर है। भोपाल, प्रदेश व देश में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र भी एजुकेशन लोन लेते हैं। एजुकेशन हब के तौर पर पहचान बना चुके भोपाल में कई बड़े संस्थान हैं। देश के अलग-अलग शहरों से बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ने के लिए भोपाल आते हैं। उनका फोकस भी एजुकेशन लोन पर रहता है। कोरोना का असर लोकल एजुकेशन लोन पर भी दिखने लगा है। आमतौर पर बैंक हर साल मार्च से सितंबर तक बड़ी संख्या में छात्रों को एजुकेशन लोन देते हैं। इस साल कोरोना के कारण ज्यादातर शिक्षण संस्थान बंद हैं, जो खुल भी रहे हैं, उन संस्थानों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने में देर है। इस वजह से एजुकेशन लोन में तकरीबन 70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे संस्थान खुलेंगे और एडमिशन होंगे, एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।

दो दर्जन भी नहीं पहुंचा आंकड़ा

यूनियन बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि मार्च 2019 से सितंबर 2019 तक करीब 100 से ज्यादा एजुकेशन लोन हुए थे, लेकिन इस साल यानी 2020 में आंकड़ा दो दर्जन भी नहीं पहुंचा है। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक में भी एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या में काफी कमी आई है।

बिजनेस और नौकरियों पर पड़ा असर

बताते हैं कि कोविड के दौरान लोगों के बिजनेस और नौकरियों पर असर पड़ा है। लिहाजा लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़े, इसके लिए लोग एजुकेशन लोन की तरफ आकर्षित होंगे। इस समय एजुकेशन लोन के लिए ज्यादा आवेदन नहीं आ रहे हैं। आने वाले आवेदन पिछले साल की तुलना में काफी कम हैं।

पहले भी लोन कम हुआ था

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश के अलग-अलग बैंकों ने 111 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन दिया था। उससे पहले 2018-19 में 153 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन दिया था। उस हिसाब से पिछले साल बैंकों के एजुकेशन लोन में करीब 42 करोड़ रुपए की कमी आई थी। इस बार एजुकेशन की लोन राशि में भारी कमी की संभावना है। प्रदेश में बैंकों की कुल संख्या 7958 है।

चार लाख से शुरू होता है एजुकेशन लोन

एजुकेशन लोन चार लाख से शुरू होता है। छात्र या फिर उनके माता पिता को उस बैंक से एजुकेशन लोन लेना आसान होगा, जहां उनका खाता हो। बच्चा जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है, वह सरकार से मान्यता प्राप्त हो। एजुकेशन लोन दो प्रकार का होता है। एक-देश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई के लिए और दूसरा विदेश में पढ़ाई करने के लिए। चार लाख से एजुकेशन लोन की शुरुआत होती है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा भी दिया जाता है। एजुकेशन लोन के लिए हर बैंक अपने-अपने हिसाब से ब्याज दर तय करता है।

कोरोना के चलते मध्यप्रदेश में एजुकेशन लोन में कमी आई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी इसमें तेजी आएगी, क्योंकि एडमिशन प्रोसेज तेज हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन लोन मिल पाए। हालांकि राज्य में पिछले साल भी कम लोगों ने एजुकेशन लोन लिया था।

एसडी माहुरकर, समन्वयक, राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी

रेसिंग चैंपियन कबूतर

कीमत 14.15 करोड़ रु.

न्यू किम नाम के कबूतर ने नेशनल मिडल डिस्टेंस रेस भी जीती है, चीन में कबूतरों की रेस काफी लोकप्रिय है

लंदन, जेएनएन। बेल्जियम के एक रेसर कबूतर को रिकॉर्ड 19 लाख डॉलर में बेचा गया है। दो साल की इस मादा कबूतर का नाम न्यू किम है। पहले इसे 237 डॉलर पर नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन चीन के एक व्यक्ति ने इसे 19 लाख डॉलर में खरीद लिया। भारतीय मुद्रा में ये रकम 14 करोड़ 15 लाख रुपये से भी ज्यादा पड़ती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कबूतर को पालने वाले कुर्त वाउवर ने बताया कि खबर सुनकर वह और उनका परिवार हैरत में पड़ गए। इससे पहले का रिकॉर्ड एक चार साल के नर कबूतर के नाम था जो 14 लाख डॉलर में बिका था। अरमांडो नाम के रेसिंग चैंपियन कबूतर को कबूतरों का लुईस हैमिल्टन भी कहा जाता था। उसके रिटायर होने के बाद 2019 में उसे बेचा गया। वहीं, न्यू किम ने 2018 में कई मुकाबले जीते, जिसमें नेशनल मिडल डिस्टेंस रेस भी शामिल है। उसके बाद से न्यू किम भी रिटायर हो गई है। पिछले कुछ सालों में चीन में कबूतरों की रेस काफी लोकप्रिय हो रही है। अरमांडो की तरह न्यू किम को खरीदने के लिए दो चीनी खरीददार एक से बढ़कर एक बोलियां लगा रहे थे। रेसिंग कबूतर 10 साल की उम्र होने तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि न्यू किम को भी उसके नए मालिक प्रजनन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नीलामी करने वालों का कहना है कि इस बात की वजह से ये नीलामी और असाधारण हो जाती है। नीलामी संस्था पीपा के सीईओ निकोलास ने बताया, ये रिकॉर्ड कीमत अविश्वसनीय है, क्योंकि ये एक मादा कबूतर है। अक्सर, नर कबूतर की कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। निकोलास ने बताया कि बेल्जियम में लगभग 20 हजार कबूतर पालक रहते हैं।

अब रहस्यमयी संगठन नहीं रहा आरएसएस समय के साथ खुद को बदला

संघ के 95 साल पूरे, फीडबैक के हिसाब से हो रहा है बदलाव

अपने सहयोगी संगठनों के विस्तार पर भी कर रहा है काम

नई दिल्ली, जेएनएन। संघ के 95 साल पूरे होते वक्त बार-बार यह सवाल पूछा जाता है कि क्या संघ बदल रहा है? क्या संघ वक्त के साथ बदलाव के लिए तैयार है? क्या संघ फ्लेक्सीबल संगठन है या कट्टरपंथी संगठन है? किसी भी संगठन के लिए करीब सौ साल का सफर अहम होता है। एक जमाने तक आरएसएस पर रायसीना हिल से एक बार नहीं, तीन-तीन बार पाबंदी लगी। हालांकि वक्त का पहिया घूमा, समय चक्र तेजी से चल रहा था। आज संघ के लोग रायसीना हिल पर काबिज हैं। जो लोग समय को नहीं समझ पाते, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है और जो वक्त से लड़ाई में नहीं हारते, वक्त उन्हें अपने सिर पर बिठा लेता है। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और दर्जनों मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और कई महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं, जिनकी राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की ट्रेनिंग संघ में हुई। संघ का नेटवर्क भारत से बाहर चालीस से ज्यादा देशों में फैल गया है। करीब सौ साल पूरे होने को है, लेकिन संघ का रास्ता अब भी संस्कार, समाजसेवा और राष्ट्रवाद से होकर जाता है, यह अलग बात है कि बहुत से लोग जब अपने चश्मे से देखते हैं तो उन्हें कुछ और सूरत और इरादे नजर आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव सुनील आंबेकर कहते हैं कि संघ जैसे-जैसे बढ़ रहा है, जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वयंसेवक पहुंच रहे हैं। यह स्वाभाविक विकास है, लेकिन संगठन में अभी बहुत सा काम करना है। आंबेकर कहते हैं कि संघ समाज पर शासन करने वाले संगठन के तौर पर नहीं रहना चाहता, बल्कि समाज को ताकतवर बनाना चाहता है, ताकि वो अपनी परेशानियों का रास्ता खुद ढूंढ सके। इसके लिए नया नारा दिया गया - 'संघ समाज बनेगा' यानी जब संघ और समाज एकाकार हो जाएं, एक हो जाएं। संघ अपने संगठनों और कार्यक्रमों के लिए फीडबैक तरीके को भी अपनाता है और निचले स्तर तक इसकी व्यवस्था है। फीडबैक के हिसाब से उसमें बदलाव के लिए भी संघ न केवल तैयार रहता है, बल्कि उसमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं।

अब पर्यावरण और जल संकट पर फोकस

इक्कीसवीं सदी के हिसाब से आरएसएस ने ना केवल खुद के स्वरूप को बदला है, बल्कि अपने कार्यक्रमों और मुद्दों के फोकस में भी बदलाव किया है। अब संघ ने नया कार्यक्रम पर्यावरण और जल संकट को लेकर शुरू किया है। इस वक्त संघ का प्रमुख एजेंडा ग्राम विकास है। आरएसएस ने पिछले पच्चीस साल में अपने सहयोगी संगठनों के विस्तार पर काम किया, साथ ही कोशिश की है कि इन संगठनों का काम ना केवल सामाजिक कार्य और सेवा हो बल्कि उनका असर सरकारों के नीतिगत फैसलों पर भी पड़े और सरकारें इसके लिए जरूरी बदलाव करे। हर संगठन अपने क्षेत्र के काम के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। अब आरएसएस को एक रहस्यमयी संगठन नहीं कहा जा सकता है, उसने दरवाजे खोले हैं, ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह हो गया है।

आज की स्थितियां देखेंगे तो कोई भी राष्ट्रीय समस्या लीजिए, संघ ने उस पर अपना रुख स्पष्ट किया है, फिर वह चाहे महिलाओं का मामला हो, सामाजिक समरसता का विषय रहा हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी सत्ता में है, इसलिए हुआ है। कांग्रेस के कमजोर होने, समाजवादियों के सिकुड़ने और लेफ्ट के लगभग गायब होने से राजनीति के क्षेत्र में जो खालीपन आया, वैक्यूम बना, संघ ने उसे भर दिया है।

- अनिरुद्ध देशपांडे, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख

किस तरह के हुए बदलाव

आरएसएस भारत की परिवार इकाई और गृहस्थ व्यवस्था को अच्छे से समझता है और उसकी ताकत को काम में लेता है। परिवारों में होते बदलावों, तेजी से बढ़ती तलाक दर, परेशानियों, टूटते परिवारों की समस्या को भी उसने समझा है। वो औरत और पुरुष को परिवार में बराबरी के हक के पक्ष में है और महिलाओं के योगदान को कम नहीं आंकता। वो परिवारों में रिश्तों की मजबूती पर काम करता है। इसके लिए परिवारों के साथ कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। संघ पारिवारिक हिंसा और महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ है। संघ अंतरजातीय विवाहों के पक्ष में है, लेकिन फिलहाल 'लिव-इन-रिलेशनशिप' के विरोध में खड़ा दिखाई देता है। संघ का मानना है कि उन देशों या समाजों में जहां मजबूत परिवार व्यवस्था नहीं हैं, वहां तो 'लिव-इन-रिलेशनशिप' को समझा जा सकता है, लेकिन भारत में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि लिव-इन-रिलेशनशिप' में बाद में शादी में बंधने के बजाय टूटते हैं और इसका मानसिक और शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है। प्रेम विवाह में भी जब लड़का-लड़की एक दूसरे को जानते हैं तो फिर 'लिव-इन' की क्या जरूरत है, यानी संघ इस व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन 'होमोसेक्सुएलिटी' के विरोध में नही हैं। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देता है और शायद हमारे यहां सबसे ज्यादा अंतरजातीय विवाह हुए हैं, लेकिन संघ फिलहाल 'इंटररिलीजन' शादियों पर काम करता नहीं दिखाई देता। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को होमोसेक्सुअलिटी को गैर-अपराध घोषित किया था लेकिन इससे दो साल पहले संघ के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इंडिया टुडे कॉनक्लेव में 17 मार्च 2016 में कहा था, 'मैं नहीं समझता कि होमोसेक्सुएलिटी को अपराधिक कार्य माना जाए, जब तक कि इसका असर समाज के दूसरे लोगों पर न पड़े।'

डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हाशिये पर जी रहे लोग

मप्र सहित 8 राज्यों में सीएसआर के तहत टीसीएस चला रही है योजना

नई दिल्ली, जेएनएन। कोरोनावायरस महामारी की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया, तब राजस्थान के भरतपुर जिले के एक गांव एकता में लक्ष्मी न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों को डिजिटल सेवाएं दे रही थीं। वह आर्थिक रूप से पिछड़े और निरक्षर लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत मिलने वाले पैसे दिलाने में मददगार साबित हो रही थीं। उनके जैसे कुछ और डिजिटल उद्यमियों ने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण उद्यमियों ने कई बैंकों के साथ जुड़कर गांव में लोगों को बैंकिंग सेवाएं भी देनी शुरू कर दीं। इन उद्यमियों में एक सामान्य बात यह है कि इन्होंने कुछ साल पहले तक कंप्यूटर कभी नहीं चलाया था और इनका ताल्लुक अति पिछड़े वर्ग से है। सामाजिक और आर्थिक तौर पर हाशिये पर जी रहे अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के सपने को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद से साकार कर रही है, जिसमें नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गनाइजेशंस (नैक्डोर) प्रमुख है। टीसीएस इसके लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग देती है, जबकि नैक्डॉर का पूरा काम जमीनी स्तर पर पिछड़े लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्यमी बनाने का होता है। नैक्डॉर ही अध्ययन और प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्री भी तैयार करता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत टीसीएस ने इस ब्रिजआईटी योजना की शुरुआत 2014 में गरीब एवं बेरोजगार युवाओं के जरिए की, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान में किया जा रहा है और अति पिछड़े वर्ग के बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को डिजिटल उद्यमी बनाया जा रहा है।

सामूहिक आमदनी 68 लाख रु. सालाना

नैक्डॉर के प्रमुख अशोक भारती कहते हैं, इन उद्यमियों की सामूहिक आमदनी जो साल 2014 में मात्र 20 हजार रुपये थी, वह 2019 में बढ़कर 68 लाख रुपए सालाना से अधिक हो गई, जबकि इसी दौरान इनकी व्यक्तिगत औसत आमदनी 4000 रुपये से दस गुना बढ़कर 40,500 रुपए से अधिक हो गई। सकारात्मक बात यह है कि ये उद्यमी खुद भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इनके परिवार में यह पहली पीढ़ी है जिसने पढ़ाई करने के साथ-साथ उद्यमी बनने की कोशिश की है। ब्रिजआईटी की लाभार्थियों में से एक लक्ष्मी कहती हैं, मैं जब इस योजना से जुड़ी तब मुझे लैपटॉप और बिजनेस किट दिया गया, जिसकी किस्त मुझे शुरुआत में देनी पड़ी। अब मैं फॉर्म भरवाने, फोटो स्टेट के अलावा कई डिजिटल सेवाएं देकर 30,000-40,000 रुपये कमा लेती हूं। राजस्थान के ही भरतपुर में रहने वाले कमल सिंह की डिजिटल प्रिंटिंग की एक दुकान है और वे लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि बनाने जैसी सेवाएं भी देते हैं। उन्होंने बताया, संस्था ने जो भी बिजनेस किट दिया, उसके लिए उन्हें निरक्षर लोगों को पढ़ाने के साथ-साथ स्कूलों में भी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) के लिए भी काम करता हूं। नालापल्ली कहते हैं कि इन उद्यमियों ने पिछले पांच सालों में एक हजार से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने के साथ 9 हजार से अधिक निरक्षर प्रौढ़ महिला-पुरुषों को निशुल्क कंप्यूटर के जरिये साक्षर बनाया है।

क्या है ब्रिजआईटी का मॉडल

टीसीएस उद्यमियों को लैपटॉप देने के साथ ही दो साल तक भत्ता भी देती है और प्रशिक्षण देकर उद्यम लगाने में भी मदद करती है। इसके बाद तीन सालों तक नैक्डोर ही उनकी जरूरत के हिसाब से समय-समय पर प्रशिक्षण देकर उनके उद्यम के संचालन में मदद देता है। भारती कहते हैं कि इस योजना में 75 फीसदी उम्मीदवारों को एससी-एसटी वर्ग से ही लिया जाता है, जबकि 25 फीसदी उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग, सवर्ण या अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं, लेकिन एक शर्त इनके साथ भी बनी होती है कि ये आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे। भारती कहते हैं, पहले हम यह देखते थे कि उम्मीदवार को कंप्यूटर आता है या नहीं, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि इस शर्त से अति पिछड़े लोग इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के लिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जिन गांवों में 30-35 फीसदी एससी-एसटी आबादी होती है, हम उन्हें ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसका मकसद यह भी है कि प्रशिक्षण के बाद जब ये लोग अपना उद्यम शुरू करें, तब इन्हें अपने ही तबके के ग्राहक भी मिल जाएं। सात उद्यमियों के कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी एक प्रमुख उद्यमी को दी जाती है, जिसे क्लस्टर लीड कहते हैं और वह इस संस्था के लिए भी एक तरह से उद्यमी ही होते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि ये सात उद्यमी सफलतापूर्वक अपना काम करें। ऐसे चार क्लस्टर एक मॉड्यूल बनाते हैं और ऐसे मॉड्यूल के देखरेख की जिम्मेदारी भी एक व्यक्ति पर होती है, जिसे मॉड्यूल लीड कहते हैं और इस एक संरचना से 33 लोग जुड़े होते हैं।